RNI NO.: UPHIN/2010/32733

ग्राम भारती

कृषि, ग्राम विकास, सहकारिता और पंचायतीराज का पाक्षिक

वर्ष : 11 अंक : 08 लखनऊ, शनिवार 01 अगर्स्त 2020 मूल्य 5 रुपये पृष्ठ : 8

उत्तर प्रदेश में एफपीओ नीति शीघ्र बनेगी, प्रारूप तैयार: शाही

लखनऊ (उ.प्र. समाचार सेवा)। उत्तर प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति 2020 बनेगी। इसके प्रारुप पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सहयोगी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ 15 जुलाई को चर्चा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के प्रगतिशील किसानों का एक समूह बनाकर उसे जिलों में भेजा जाए, यह समूह किसानों को एफपीओ के लाभ बताए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-80 में

कृषि कार्यों में कृषक उत्पादक संगठनों की आवश्यकता, उनकी भूमिका एवं महत्ता के बारे में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 के प्रारूप पर भी विचार विमर्श किया गया। वर्तमान परिवेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने, कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन में कृषक उत्पादक संगठनों की अहम भूमिका हह्य। श्री शाही ने कहा कि 20 प्रगतिशील एवं अनुभवी किसानों का एक समूह बनाया जाए, जो विभिन्न जनपदों में भ्रमण कर किसानों को कृषक उत्पादक संगठनों के प्रति जागरूक करेगा। कहा कृषि विभाग एवं अन्य सम्बद्ध विभागों के अलग-अलग एफपीओ बनाये जायेंगे, जिनका नोडल कृषि विभाग होगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 447 से अधिक कृषक उत्पादक संगठन कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत हैं। इसमें उ.प्र. भूमि सुधार निगम के अन्तर्गत 120, नाबार्ड के अंतर्गत 273 तथा उ.प्र. जैव ऊर्जा बोर्ड के अंतर्गत 134 कृषक उत्पादक संगठन गठित हैं। प्रदेश में कुल 2 करोड़ 38 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से 93 प्रतिशत छोटे किसान हैं। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, कृषि निदेशक सोराज सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 92वां स्थापना दिवस मनाया

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विकास में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, उन्हें सुनिश्चित करना है कि अनुबंधित कृषि का लाभ छोटे किसानों को भी मिले

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 16 जुलाई को अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की, जिनके कारण आईसीएआर ने पिछले नौ दशकों के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान में वैज्ञानिकों के अंशदान और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते भारत आज अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाला देश बन गया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान भी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए देश के किसानों को बधाई दी। श्री तोमर ने वैधानिक संशोधन और अध्यादेशों की घोषणा के द्वारा बहुप्रतीक्षित कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया है, जिससे किसान सशक्त होंगे और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य हासिल करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि

आयात पर निर्भरता घटाने, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की है जरूरत : श्री तोमर

आईसीएआर और कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि अनुबंधित कृषि का लाभ छोटे किसानों को भी मिले।

वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि 10 दशक में पूसा संस्थान (आईएआरआई) एक राष्ट्रीय संस्थान से अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने, स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों के साथ ही दालों व तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री तोमर ने कहा कि अनुसंधान के द्वारा पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने तिलहन की नई किस्में ईजाद करने पर भी जोर देते हुए कहा कि दलहन उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता हासिल करने के करीब हैं और उम्मीद है कि तिलहन के मामले में भी हम ऐसी ही सफलता को दोहराएंगे और खाद्य तेलों के आयात पर होने वाले खर्च में कमी ला पाएंगे।

इस अवसर पर 8 नए उत्पादों का लोकार्पण और 10 प्रकाशनों का विमोचन किया गया। केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, आईसीएआर के कई वैज्ञानिक और अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

हेलीकॉप्टर से टिड्डी नियंत्रण अभियान

भारत सरकार के अनुसार देश में 11 अप्रैल, 2020 से टिड्डी नियंत्रण अभियान शुरु किया गया है। 16 जुलाई तक 1,76,055 हे. क्षेत्र में टिड्डी सर्कल कार्यालयों (एलसीओ) द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया।

भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर को राजस्थान में बाड़मेर के रामसर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान में लगाया गया।

भीतर पढ़ें

खेत-खलिहान

अगस्त माह के कृषि कार्य

पंचायत प्रतिनिधि साक्षात्कार

♦ब्लाक प्रमुख मुरादाबाद मनीष सिंह पृष्ठ चार पर

♦ग्राम प्रधान हबीबपुर सीतापुर नीलम शुक्ला पृष्ठ चार पर

♦ग्राम प्रधान खोराडीह रामेश्वर सिंह पृष्ठ पांच पर

सम्पादकीय

टिड्डी दलों का कहर,बेहाल किसान

पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों ने उत्तर और मध्य भारत के किसानों को बेहाल कर दिया है। इन दलों ने देश की कृषि उपज पर आक्रमण करके कई लाख हेक्टेयर फसलों को चट कर दिया है। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश,दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। टिड्डी दलों ने कई लाख हेक्टेयर फसलें चट कर ली हैं। भारत में टिड्डी दल ने जनवरी से फरवरी के बीच राजस्थान की सीमा में पाकिस्तान से प्रवेश किया था। इसके बाद यह दल पूरे राजस्थान में फैल गया। मई महीने में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में प्रवेश कर गया। इसके बाद हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गया। टिड्डी दल जून और जुलाई तक एनसीआर और उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले चुका था। देश का किसान पहले ही अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से त्रस्त था, ऊपर से लाकडाउन होने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है। इसी में यह टिड्डी दल की आफत आ गई। लाकडाउन के चलते केन्द्र और राज्य की सरकारों ने टिड्डी दलों के आक्रमणों पर सिर्फ किसानों को परामर्श जारी किये, कोई ठोस उपाय उन्हें रोकने और नष्ट करने के लिए नहीं किये गए। न तो ठीक से रसायन का छिड़काव किया गया और न ही समूचित और संगठित ढंग से कृषि अधिकारियों ने काम किया। परिणाम स्वरूप किसानों को एक और आफत का सामना करना पड़ गया। इससे हुई क्षति का ठीक से आकलन भी नहीं किया गया है। कई राज्यों में किसानों को मुआवजा देने की मांग उठी है। हरियाणा में विपक्ष ने मांग की है कि किसानों को टिड्डी दल से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के रूप में 40 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रदान किये जाएं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की है। किन्तु सबसे बड़े प्रदेश और सर्वाधिक किसान संख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। सिवाय इसके कि कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आपदा निधि से किसानों को राहत पहुंचाएं।

गाजर घास का कहर

प्रदेश के किसानों पर गाजर घास का कहर बरप रहा है। कृषि विभाग ने यदि समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए तो अन्नदाता जंगली घास के चलते निश्चित तौर पर बदहाली का शिकार हो जाएगा। गाजर घास के कहर से किसानों को तो दो-चार होना ही पड़ेगा यह जहरीली घास वातावरण को दूषित करने के साथ-साथ मानव एवं पशु-पक्षियों के लिए भी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। इस विनाशकारी खरपतवार को समय रहते यदि नियंत्रण न किया गया तो विनाश का कारण भी बन सकती है। बताते चलें कि आजकल खेतों एवं गांव के लिंक मार्गों, गांव में खाली पड़ी जमीनों पर एवं हाईवे के किनारे यह उग रही है। इस विदेशी घास से किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की माने तो यह गाजर घास मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहां हानिकारक है वहीं खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी कर रही है। इस जंगली घास के चलते इसके पौधों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थो के कारण फसलों के अंकुरण एवं वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं दलहनी फसलों में यह खरपतवार जड़ ग्रंथियों के विकास को भी प्रभावित कर रहा है । किसान बताते हैं यह पौधा वर्ष में तीन-चार माह में अपना

विदेशी जहरीली घास किसान की बनी सबसे बड़ी समस्या

जीवन चक्र पूरा कर लेता है और पूरे वर्ष खूब फलता फूलता रहता है । इसका प्रकोप खाद्यान्न फसलों जैसे धान ,ज्वार,मक्का,सोयाबीन ,मटर, तिल ,गन्ना, बाजरा ,सब्जियों एवं उद्यान फसलों में भी देखने को मिल रहा है। उक्त गाजर घास का पौधा रोएदार एवं अत्यधिक शाखा युक्त होता है ।इसकी पत्तियां असामान्य रूप से गाजर की पत्तियों की तरह होती हैं। इस उगने वाली घास में फूलों का रंग सफेद होता है । जो सूक्ष्म बीज का निर्माण करता है । यदि जानकारों की माने तो एक हजार से पांच हजार तक अत्यंत महीन सूक्ष्म छोटे-छोटे बीज के रूप में जमीन पर गिरने के बाद थोड़ी सी नमी पाकर अंकुरित हो जाता है । जानकार बताते हैं इस खरपतवार की 20 प्रजातियां हैं जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं भारत में लगभग 3 दशक पूर्व अमेरिका और कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ यह बीज आया था। उक्त घास के लगातार संपर्क में आने से एक्जिमा , एलर्जी , बुखार , दमा आदि की प्रबल आशंका बनी रहती है । खास करके दुधारु पशुओं के लिए यह घास अत्यधिक नुकसान देह है । यदि समय रहते गैर कृषि क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में इसके नियंत्रण के लिए रासायनिक एन्ट्राजिन का प्रयोग फूल आने से पहले किया जाए तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है । इसे यांत्रिक, रासायनिक , जैविक विधियों के द्वारा भी रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर अगर प्रचार-प्रसार न किया गया तो निश्चित तौर पर किसानों के साथ साथ आमजन को भी भविष्य में भयावयता का सामना करना पड़ सकता है । **संवाददाता, बिसवां, सीतापुर**

ग्राम भारती पाठक मंच

डीलर हजम कर रहे हैं गरीबों का राशन

बिजनौर में केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से गरीबों को दिए जा रहे राशन को बांटने का काम करने वाले राशन डीलर ही गरीबों का राशन बेधड़क हजम कर रहे हैं। कोरोना काल शुरु होने से अब तक जनपद के राशन डीलरों की तमाम शिकायतें हैं, जिसे लेकर जनपद का पूर्ति विभाग गंभीर नहीं है। प्राप्त विवरण के अनुसार जनपद बिजनौर में 1800 राशन डीलर हैं और जिले में करीब 6,00,000 राशन कार्ड धारक हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के समय में घोषणा की थी कि अंत्योदय कार्ड धारक, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर एवं दिहाड़ी मजदूरों को प्रत्येक राशन डीलर निशुल्क राशन देगा। बाकी राशन संबंधित डीलर को रुपये 2 किलो गेहूं व रुपये 3 प्रति किलो चावल की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। महीने में दूसरी बार सभी राशन कार्ड

लापरवाह अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं

धारकों को 5 किलो चावल प्रति सदस्य निशुल्क दिया जाएगा। लेकिन राशन डीलरों ने इसमें जनता को ठगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संबंधित राशन डीलरों ने राशन हड़पने के खेल में पहले उपभोक्ताओं के अंगूठे पोस मशीन पर लगवा लिए और यह कहकर राशन नहीं दिया कि राशन 15 तारीख के बाद बांटा जाएगा। और पंद्रह तारीख के बाद शासन से आया राशन निशुल्क बांट तो दिया, लेकिन पहले 15 दिन का गायब कर दिया गया। गरीबों के राशन का यह गबन अधिकारियों के संरक्षण में जनपद के लगभग सभी राशन डीलरों द्वारा बेरोकटोक किया जाता रहा। जबकि इस बीच हजारों की तादाद में संबंधित राशन डीलरों की शिकायतें भी हुई। राशन का यह गबन लगभग सभी राशन डीलरों द्वारा किया गया है और केंद्र व प्रदेश सरकार को चूना लगाया गया। जो जांच का बिंदु है। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि राशन का गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे राशन डीलरों की दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। **पुखराज सिंह मलिक, बिजनौर**

पात्रों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ

सीतापुर में पात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदारों द्वारा योजनाओं को अपनी आमदनी का जरिया बना लिया गया है जिसके चलते पात्र योजनाओं का लाभ पाने के लिये दर दर भटक रहे हैं। गौरतलब है कि एक तरफ सरकार गरीबों के लिए तमाम तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है और उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं कुछ लापरवाह अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कस्बे के एक मुहल्ला की रहने वाली रामलली दिव्यांग है, रामलली के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं। बड़े पुत्र का विवाह हो चुका है और वह अपने परिवार के साथ अलग रहता है। रामलली के पति शिवराज पल्लेदारी कर जर्जर मकान में रहकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। रामलली ने एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था। उन्हें आज तक आवास का लाभ नहीं मिला। वहीं दिव्यांग पेंशन के लिए वह सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश है। दूसरी ओर सोनारन टोला निवासी नवनीता व उनके पति प्रमोद दोनों ही दिव्यांग हैं। नवनीता के एक पुत्र व एक पुत्री है। वह मजदूरी कर 1500 रुपये प्रति माह कमा कर अपने परिवार को किसी तरह चला रही है। नवनीता का कहना है कि उसको शादी से पहले दिव्यांग पेंशन मिलती थी। शादी के बाद से उसको पेंशन मिलना बंद हो गई है। पति का भी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। जिससे उन्हें भी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है। **आलोक कुमार, सीतापुर**

कृषि शिक्षा के लिए पंतनगर कृषि विवि को आईसीएआर पुरस्कार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आने वाले कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अंतर्गत आने वाला स्वायत्त संस्थान है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण सोसायटी के रूप में 16 जुलाई, 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। परिषद देश भर में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। देशभर के 102 आईसीएआर संस्थान व राज्यों के 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया में सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।

आईसीएआर ने हरित क्रांति को बढ़ावा देने और इस क्रम में शोध एवं तकनीक विकास के माध्यम से भारत में कृषि विकास में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र की खाद्य और पोषण सुरक्षा पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसने कृषि में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद् हर साल संस्थानों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और कृषि पत्रकारों को मान्यता और पुरस्कार भी देता रहा है।

इस साल 20 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 160 पुरस्कारों के लिए लोगों और संस्थानों का चयन किया गया। इनमें तीन संस्थान, दो एआईसीआरपी, 14 केवीके, 94 वैज्ञानिक, 31 किसान, 6 पत्रकार और विभिन्न आईसीएआर संस्थानों के 10 कर्मचारी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि पुरस्कार हासिल करने वाले 141 लोगों में 19 महिलाएं हैं।

कृषि विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर को शिक्षण, शोध, विस्तार और नवाचार जैसे सभी क्षेत्रों में तेज प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर- केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि को बड़े संस्थान की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार, वहीं आईसीएआर- केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई को छोटे आईसीएआर संस्थानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आईसीएआर संस्थान के पुरस्कार के लिए चुना गया।

सोरघुम, हैदराबाद पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना और मक्का, लुधियाना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को संयुक्त रूप से चौधरी देवी लाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रीय स्तर पर के वीके के लिए दीन दयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जिले के कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के विकास पर विशिष्ट प्रभाव को चलाई गई उल्लेखनीय विस्तार/ आउटरीच गतिविधियों के लिए संयुक्त रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, दतिया, मध्य प्रदेश और कृषि विज्ञान केन्द्र, वेंकटरमन्नागुडेम, आंध्र प्रदेश का चयन किया गया। कृषि पत्रकारिता, 2019 के लिए छह पत्रकारों को चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया गया, जिनमें 4 प्रिंट और 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थे।

कृषि पत्रकारिता, 2019 के लिए छह पत्रकारों को चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया गया, जिनमें 4 प्रिंट और 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से

उर्वरक का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील: सदानन्द गौड़ा

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार ने बुआई के मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक क्षेत्र के लिए कई पहल की हैं।

श्री गौड़ा ने कहा कि नई निवेश नीति-2012 के प्रावधानों और 2014 में इसमें किए गए संशोधनों के तहत, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) ने राजस्थान के गढ़ेपान में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के साथ एक ब्राउनफील्ड परियोजना शुरू की है। यहां एक जनवरी, 2019 से उत्पादन शुरु हो चुका है। इससे 2019-20 के दौरान देश में 244.55 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करने में मदद मिली।

उन्होंने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने एचएफसीएल की बरौनी, रामागुंडम, तालचेर, गोरखपुर और सिंदरी की बंद उर्वरक इकाइयों को फिर से चालू करने का काम शुरू कर दिया है। यह सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इसमें से प्रत्येक इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.27 एमएमटीपीए होगी। ये संयंत्र गैस से संचालित होंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के अनुसार सभी ऐसी उर्वरक इकाइयों को जो ईंधन के रूप में नेफ्था का उपयोग कर रही हैं, उन्हें प्राकृतिक गैस से संचालित इकाइयों में परिवर्तित किया जाना है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पहले से ही नेफ्था के स्थान पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गैस पाइपलाइन से जुड़ने के बाद से इस इकाई में 29 जुलाई, 2019 से यूरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है। यह इकाई अब पूरी तरह से प्राकृतिक गैस से संचालित है।

परियोजना	समग्र प्रगति	तह्यार हो जाने की संभावित तिथि
रामगुंडम	99.58%	पूरे होने के चरण में
तालचेर	59.48%	2023 तक
गोरखपुर	88.10%	2021 तक
सिंदरी	77.80%	2021 तक
बरौनी	77.60%	2021 तक

कोरोना काल में ब्लाक के गांवों को महामारी से बचाया

ग्राम भारती से बातचीत में बोले मुरादाबाद सदर ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह

प्रस्तुति: राहुल सिंह, मुरादाबाद

मुरादाबाद। हाल ही में केन्द्र सरकार की ओर से देश में बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। इस फेहरिस्त में उत्तर प्रदेश की चार क्षेत्र पंचायतें भी शामिल हैं। जिसमें मुरादाबाद सदर ब्लाक का नाम सबसे ऊपर है। चौतरफा विकास कार्यों के चलते ओवर आल परफॉर्मेंस पर ब्लाक का चयन हुआ है। **ग्राम भारती** ने मुरादाबाद सदर ब्लाक के कार्यों की पड़ताल करने के साथ ही जिले के सबसे युवा ब्लाक प्रमुख **मनीष कुमार सिंह** से बातचीत भी की।

ब्लाक प्रमुख ने बताया कि कोरोना महामारी से ग्रामीणों को बचाने के लिए हर गांव में नियमित रूप से सेनेटाइजेशन कराया जा रहा है। हैंड सेनिटाइजर भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यही वजह है जो ब्लाक के किसी भी गांव में अब तक एक भी ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है।

बातचीत में उन्होंने बताया कि ये पहली बार है जब सदर ब्लाक को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। ब्लाक के सभी ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के अलावा अधिकारी और कर्मचारियों का भी सहयोग मिला, तभी ये सफलता हासिल हुई। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें केवल दो साल का ही कार्यकाल मिला है, इसमें महज डेढ़ साल के कार्यकाल में सभी 46 गांवों में समान रूप से विकास कराया है। इसमें सड़कों नालियों के निर्माण के अतिरिक्त स्कूलों का कायाकल्प, सौन्दर्यकरण पर काम हुआ साथ ही हर गांव को सबसे पहले ओडीएफ किया गया। प्रदेश में पहला ओडीएफ ब्लाक घोषित होने पर भी सम्मान मिला।

पंचायत प्रतिनिधि साक्षात्कार

प्रमुख ने कोविड-19 पर बताया कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए भी ब्लाक के हर गांव को सेनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा हर गांव में सेनिटाइजर स्टैंड व हैंड सेनिटाइजर ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांव के स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया जा रहा है

ताकि लोग महामारी के प्रकोप से बच सकें। उन्होंने बातचीत में बताया कि अभी हर गांव के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट/डिजिटल क्लास बनाने की तैयारी चल रही है। बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उद्घोष से प्रेरणा लेकर ही गांवों में विकास कार्य कराए गए हैं। अबकी बार पूर्ण कार्यकाल मिला तो सदर ब्लाक को प्रदेश ही नहीं देश का नंबर वन ब्लाक बनाने का प्रयास किया जाएगा।

सबका साथ सबका विकास के उद्घोष से मिली कामयाबी

कहा-महज दो साल के कार्यकाल में हर गांव में कराए विकास कार्य

देश का नंबर वन ब्लाक होगा मुरादाबाद सदर

पंचायत प्रतिनिधि साक्षात्कार

विकास से जीता गांव की जनता का विश्वास: नीलम शुक्ला

अपनी ससुराल की ग्राम पंचायत की प्रधान हूँ और बहू भी। सीतापुर जनपद के विकास खंड खैराबाद की ग्राम पंचायत अहाता कसान (हबीबपुर) की ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम शुक्ला पत्नी दिवाकर शुक्ला ने अपने कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य कराकर जनता का दिल जीतने में सफल रही या नहीं रहीं हैं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपने ग्राम पंचायत की सूरत बदलने में कोई कोर कसर छोड़ी हो। ग्राम भारती के प्रतिनिधि आलोक कुमार वाजपेयी ने उनसे बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश:-

प्रश्न:- आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

उत्तर:-जूनियर हाईस्कूल तक मैंने शिक्षा ग्रहण की है।

प्रश्न:- आप ग्राम प्रधान पद कितनी बार निर्वाचित हुई हैं ?

उत्तर:-मैं पहली बार चुनाव

आयी और निर्वाचित भी हुई।

प्रश्न:- आपका पंचायत की राजनीति में आने का कारण क्या रहा ?

उत्तर:- मेरा पंचायत के चुनावी मैदान में आने का कारण सिर्फ यही रहा कि जिन लोगों की सेवा करना तथा ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत में विकास करवाना इत्यादि।

प्रश्न:- क्या घर से बाहर निकलकर कार्य करने में आप असहज महसूस करती हैं?

उत्तर:- नहीं, मैं जहां आवश्यक होता है वहां जाती हूँ परन्तु

मैंने बहुत कुछ बेहतर किया है। आज प्रत्येक पंचायत का निवासी स्वयं बेहतरी का अनुभव कर रहा है। मैंने नाली, खड़ण्जा, सीसी रोड़, अन्तेष्टि स्थल,विद्यालय भवन, स्ट्रीट लाइट, इंण्डिया मार्का हैंण्डपम्प, पुलिया निर्माण, शौंचालय, आवास, विधवा, वृद्धावस्था व विक लांग पेंशन, राशन कार्ड इत्यादि।

अनावश्यक कहीं भी नहीं जाती हूँ। मैं अपनी ससुराल की ग्राम पंचायत की प्रधान हूँ और बहू भी।

प्रश्न:- आपने पूर्व प्रधानों से अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या बेहतर किया है?

उत्तर:- मैंने बहुत कुछ बेहतर किया है। आज प्रत्येक पंचायत का निवासी स्वयं बेहतरी का अनुभव कर रहा है। मैंने नाली, खड़ण्जा, सीसी रोड़, अन्तेष्टि स्थल,विद्यालय भवन, स्ट्रीट लाइट, इंण्डिया मार्का हैंण्डपम्प, पुलिया निर्माण, शौंचालय, आवास, विधवा, वृद्धावस्था व विक लांग पेंशन, राशन कार्ड इत्यादि।

प्रश्न:- आपके कार्यकाल में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं?

उत्तर:- मैंने आपको पूर्व के प्रश्न के जवाब में बताया है कि मैंने अधिक से अधिक कार्य अपनी ग्राम पंचायत में करवायें हैं। आज हमारे गांव के लोग स्वयं ही इस बात के साक्षी हैं।

प्रश्न:- आपके ग्राम पंचायत में कुल मतदाता कितने है व जातिवार मतदाताओं की संख्या क्या है?

उत्तर:- हमारे ग्राम पंचायत में कुल मतदात तीन हजार तीन सौ हैं, जिसमें सामान्य जाति के पचास प्रतिशत, पिछड़ी जाति के 26 प्रतिशत, व अनुसूचित जाति के 24 प्रतिशत के लगभग हैं।

प्रश्न:- आपकी ग्राम पंचायत में मनरेगा में पंजीकृत मजदूरों की संख्या कितनी है?

उत्तर:- हमारी ग्राम पंचायत में लगभग चार सौ मनरेगा के पंजीकृत मजदूर हैं।

प्रश्न:- क्या आगामी पंचायत चुनाव में पुन: प्रधान प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आयंगीं ?

उत्तर:- बिल्कुल आऊगीं।

प्रश्न:- आपके कार्यो में क्या आपके घर के लोग सहयोग करते हैं?

उत्तर:- बिल्कुल करते हैं। मेरी प्रधानी में मेरे पति, देवर, जेठ, व सास-ससुर का बहुत सहयोग मिलता है।

प्रश्न:- आपके कुछ सहयोगी आपसे नाराज हो गये होंगें और कुछ नये सहयोगी बन गये होंगें! ऐसी परिस्थिति में आप पहले का समय बेहतर मानती हैं या वर्तमान समय का ?

उत्तर:- ऐसा तो चलता रहता है, लेकिन जो मेरा वर्तमान समय का समय व सहयोगी हैं, वही सही लगता है।

कभी रहा नक्सलवाद का पर्याय, आज विकास में कर रहा है आदर्श स्थापित

रंग ला रही है ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह की मेहनत, मिल रही है सराहना, हरियाली से घिरा निर्मल-आदर्श तालाब, जल संचय का पेश कर रहा है मिसाल

रिपोर्टः संतोष देव गिरि, मीरजापुर

उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जनपदों में शुमार रहे मीरजापुर जिले का नाम आते ही एक समय अच्छे-अच्छे की सांसे थम जाती थीं। वजह बताया जाता था इस जनपद का नक्सलवाद से जुड़ा हुआ नाता खासकर, मिजार्पुर के मड़िहान तहसील क्षेत्र का इलाका अत्यधिक नक्सल प्रभाावित क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन, कालांतर में सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं और लोगों की सोच में होने वाले परिवर्तन से जहां इस जनपद का नक्सलवाद से नाता टूट चुका है। वहीं, जो लोग नक्सलवाद से नाता जोड़ कर चल रहे थे वह अब समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर नए सिरे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात जब छिड़ती है जिले के राजगढ़ विकास खंड अंतर्गत 'खोराडीह गांव' की तो बरबस ही खोराडीह गांव का नाम और पीएसी कैंप पर नक्सलियों द्वारा बोला गया हमला याद आ जाता है। आखिरकार याद आए भी क्यों ना। आज से तकरीबन डेढ़ दशक पूर्व नक्सलियों ने खोराडीह गांव स्थित पीएसी कैंप पर धावा बोलकर कई प्रमुख असलहे लूट ले गए थे। इस घटना के बाद पूरा शासन-प्रशासन हिल उठा था। पुलिस द्वारा की गई कांबिंग के बाद भी नक्सलियों द्वारा लूट लिए गए असलहे पुलिस के हाथ लग नहीं पाए थे। इस घटना के

बदलाव की बयार...
'खोराडीह गांव'

बाद ग्रामीणों में नक्सलियों का भय इस कदर समा गया था कि शाम ढलते ही ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाने को विवश हो जाते थे। आज यही खोराडीह गांव बदलते जमाने के साथ कदमताल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस गांव में बदलते जमाने के साथ ही बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। खासकर इस गांव को नक्सलवाद के कलंक से मुक्ति मिल चुकी है तो वहीं दूसरी ओर गांव में आने के लिए मुख्य मार्ग से गांव तक पक्की सड़क, पेयजल के लिए हैंडपंप, स्वच्छता अभियान को साकार करता हुआ घर-घर शौचालय इत्यादि इस गांव की सोच और चौमुखी विकास की तस्वीर को करीब से रूबरु कराती है। आदर्श ग्राम पंचायत खोराडीह ग्राम विकास की योजनाओं, स्वच्छता इत्यादि के साथ - साथ पौधरोपण के मामले में भी आदर्श स्थापित कर रहा है। यह सब कुछ गांव के होनहार ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह के कुशल निर्देशन में एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की गाइड लाइन के मुताबिक संपन्न हो रहा है। यह गांव न केवल कई गांव के लिए विकास का माडल व नजीर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, बल्कि इस गांव से कई लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं। जिले के अंतिम छोर पर बसा हुआ राजगढ़ विकास खंड अंतर्गत खोराडीह गांव कभी नक्सलियों की धमक से सहमा हुआ करता था, लेकिन कालांतर में यह गांव विकास के माडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां के विकास परियोजनाओं को देख कई लोग इस गांव को नजीर के रूप में लेते हुए अपने गांव का ड्डी कायाकल्प कुछ खोराडीह गांव की भांति करने

आज 'खोराडीह गांव' बदलते जमाने के साथ कदमताल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस गांव में बदलते जमाने के साथ ही बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। खासकर इस गांव को नक्सलवाद के कलंक से मुक्ति मिल चुकी है तो वहीं दूसरी ओर गांव में आने के लिए मुख्य मार्ग से गांव तक पक्की सड़क, पेयजल के लिए हैंडपंप, स्वच्छता अभियान को साकार करता हुआ घर-घर शौचालय इत्यादि इस गांव की सोच और चौमुखी विकास की तस्वीर को करीब से रूबरू कराती है।

प्रधान रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में गांव को मिल चुका है सम्मान

मीरजापुर के खोराडीह गांव को स्वच्छता और विकास की दिशा में बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह को सम्मानित भी किया गया है। 'ग्राम भारती' प्रतिनिधि से बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह गांव

आत्मनिर्भरता की ओर बढ रही हैं महिलाएं

रामेश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व और इस गांव को विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर कई उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। जनपदीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के बेहतर समन्वय एवं ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह की दृढ़ लगन और संकल्प का प्रतिफल ही कहा जाएगा कि देश की राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गुजरात में आयोजित समय-समय पर विभिन्न ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों में इस गांव की ना केवल सहभागिता सुनिश्चित की गई है, बल्कि बेहतर कार्यों के लिए इस गांव की मंच से सराहना करते हुए ग्राम प्रधान रामेश्वर के समग्र विकास की दिशा में बढ़ते कदम के साथ ही इस दौरान होने वाली तमाम परेशानियों को भी बड़े ही सलीके के साथ प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि गांव में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर वह कई लोगों की आंखों की किरकिरी भी बने। उन पर सुनियोजित हमले की भी साजिश रची गई कुछ मामलों में फंसाने का भी कुचक्र रचा गया, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ हौसले और विश्वास तथा ग्रामीणों के सहयोग के बलबूते ना केवल इसे विफल किया है, बल्कि विपक्षियों के भी मंसूबों पर पानी फेरते आए हैं। ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह कहते हैं कि उन्होंने गांव के विकास और ग्रामीणों के उत्थान की दिशा में

बिना किसी भेदभाव और दलगत, जातिगत भावना से ऊपर उठकर कार्य किया है। यही कारण है कि आज यह गांव जिले में मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

की प्रेरणा ले रहे हैं। ग्राम सुरक्षा समिति, ग्राम पंचायत सदस्य व समाजसेवी संस्था के सदस्यों, श्रमिकों द्वारा तालाब के तथा सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। जिसमें 75 प्रतिशत फलदार पौधों को लगाया जा रहा हैं। जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान रामेश्वर सिंह ने बताया है कि कुल लगभग दस हजार पौधे लगाने का लक्ष्य है, जो सबके सहयोग से किया जा रहा है। कहा वृक्षारोपण एक पुनीत का कार्य है। बताया कि खोराडीह में मनरेगा योजना अंतर्गत पिछले वर्षो में करायें गये वृक्षारोपण जिनमें 95 प्रतिशत पौधा जीवित व विकास के तरफ अग्रसर है, शेष 5 प्रतिशत का पुनः उसी स्थान पर पौधरोपण कर 100 प्रतिशत पौधों को जीवित रखने का संकल्प लेते हुए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा की भांति इस बार भी ग्राम पंचायत खोराडीह तत्पर हैं। इस गांव ने लॉकडाउन अवधि में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में भी बेहतर कार्य किया है।

लाभप्रद है अगस्त माह, खरपतवार प्रबंधन के साथ करें निराई

*संतोष देव गिरि

इस वर्ष मानसून बेहतर होने के नाते किसानों के लिए खासकर धान की खेती करने वाले और दलहनी, तिलहनी फसलों से लेकर साग सब्जी की खेती किसानों के लिए लाभप्रद है। बशर्ते किसान भाई कुछ खास विषय बिंदुओं पर ध्यान देते हुए खेती-किसानी करें तो लाभ ही लाभ है। कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस साल मानसून अच्छा होने के नाते खेती किसानी में भी कुछ खास बातों पर सावधानियां बरतते हुए किसान भाई खेती के जरिए लाभान्वित हो सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त महिना खरपतवार प्रबंधन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। खासतौर पर धान की खेती के लिए, वह इसलिए कि अगस्त महीने में बरसात

अगस्त माह के कृषि कार्य

अपेक्षाकृत कम होने के साथ ही धान के खेतों में उगने वाले खरपतवार भी कम होने लगते हैं जिनकी समय से निराई कर दी जाए तो धान की फसलों को बढ़ाने में तथा विकास करने में बेहतर लाभ होता है।

उर्वरक प्रबंधन: अगस्त का महीना साग सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त होता है, जुलाई का महीना समाप्त होने के बाद अगस्त का महीना प्रारंभ होते ही खाद की पहली डोज देने से पूर्व खेतों की निराई कर देनी चाहिए। इससे खेतों

खेत-खलिहान

की उर्वरा क्षमता बने होने के साथ-साथ खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं और पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। इस सीजन में उगाए जाने वाले लौकी, कोहड़ा (सीताफल), करैला, बोड़ा के पौधे के आसपास गुड़ाई करने के साथ ही प्रथम सप्ताह में मिट्टी की चढ़ाई कर देनी चाहिए, ताकि पौधों मजबूत बने रहें और उनके आसपास खरपतवार भी नष्ट हो जाएं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में लौकी, करेला, बोड़ा इत्यादि के पौध में बेल निकल आते हैं। ऐसे में बिना किसी देर के बांस बल्ली लगाकर इनके बेल को उन पर चढ़ा देना चाहिए, इससे इनके पैदावार में सुगमता होती है और यह जमीन पर लुढ़कते नहीं हैं। इतनी मेहनत के बाद किसान को अच्छी पैदावार के साथ ही साथ फसल की रखवाली में भी सुगमता होती है।

यह कीड़े मकोड़ों से खासकर जमीन पर पड़े रहने की अवस्था में नष्ट होने से भी बच जाते हैं। इसी प्रकार अगस्त में यदि खेतों में मिर्च, बैगन, गोभी, टमाटर की नर्सरी पड़ गई है तो मौसम अनुकूल देख इनका रोपण भी कर देना चाहिए, ताकि यह विकास कर सकें।

खेती-किसानी से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि अगस्त में मौसम अनुकूल होने पर इनके रोपण में देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि खरपतवार अंतिम स्टेज पर होता है बरसात भी अपेक्षाकृत कम होती है ऐसे में खेतों को बेहतर ढंग से तैयार कर मिर्ची, टमाटर, गोभी इत्यादि के पौधों का रोपण करने में देर नहीं करनी चाहिए।

'अगस्त माह' में खरपतवार प्रबंधन और उर्वरक पर विशेष ध्यान दें: डा. एस एन सिंह

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा (मिजार्पुर) स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ एस.एन. सिंह कहते हैं कि किसान भाइयों को

अगस्त महीने में खरपतवार प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन का विशेष ध्यान देते हुए मौसम की अनुकूलता का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, उन्हें कई फायदे हो सकते हैं। मौसम की अनुकूलता और उचित प्रबंधन के जरिए किसान साग सब्जियों की खेती के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। वह कहते हैं कि किसान भाई इस संबंध में राजीव गांधी दक्षिणी परिसर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से भी विविध प्रकार की आधुनिक तकनीकी ज्ञान अर्जित कर खेती किसानी से जुड़े हुए परामर्श को सुलभता के साथ प्राप्त कर सकते हैं।

दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए उपयुक्त समय: प्रो. राम सिंह

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा (मिजार्पुर) स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राम सिंह बताते हैं कि इस सीजन में लगातार हो रहे बरसात से खेतों में भरपूर नमी बने होने के कारण कम पानी वाली फसलों के लिए अगस्त का महीना

बेहतर महीना है। वह बताते हैं कि खरीफ की फसलों में बहुत सी फसलें सूखे में बोई जाती हैं। बरसात कम होने के बाद अगस्त के महीने में खेतों में नमी बनी रहती है, ऐसे में किसान भाई दलहनी एवं तिलहनी

कृषि विशेषज्ञ परामर्श

फसलों मसलन, तिलहन की खेती बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसी प्रकार दलहनी फसलों में उड़द, मूंग की बुवाई कर नगदी फसल की खेती कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं।

खाद की 65 दुकानों पर पड़े छापे, 25 संदिग्ध उर्वरकों के नमूनें ग्रहीत, 9 दुकानें निलम्बित

सीतापुर (उ0प्र0 समाचार सेवा)। प्रमुख सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन के अनुपालन में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में विभिन्न तहसीलों हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के साथ 6 टीमों का गठन करते हुए रासायनिक उर्वरकों के निजी, सहकारी प्रतिष्ठानों पर अभिलेखों का मिलान स्टाक के अनुसार तथा गुणवत्ता परीक्षण हेतु उर्वरक नमूने एवं आकस्मिक छापे डालने के निर्देश दिये। अरविन्द मोहन मिश्र, उप कृषि निदेशक उर्वरक निरीक्षक तहसील बिसवॉ अखिलानन्द पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी उर्वरक निरीक्षक तहसील सदर लहरपुर श्यामनरायन राम, जिला कृषि रक्षा अधिकारी उर्वरक निरीक्षक तहसील महमूदाबाद राजितराम, भूमि संरक्षण अधिकारी, महोली अख्तर हुसैन, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर उर्वरक निरीक्षक तहसील मिश्रिख द्वारा जनपद के आवंटित तहसीलों में नामित उर्वरक निरीक्षकों

जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय न किया जाये, किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाय।

सीतापुर उर्वरक निरीक्षक तहसील सिधौली 5-श्री रामकुमार यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी महोली-सीतापुरध्उर्वरक निरीक्षक तहसील के द्वारा उर्वरक की दुकानों पर छापे डालने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही में कुल 65 दुकानों, प्रतिष्ठानों, कम्पनी के बफर गोदाम आदि पर छापे डाले गये जिसमें से 25 संदिग्ध उर्वरको के नमूने ग्रहीत किये गये, तथा 9 दुकानों को निलम्बित किया गया। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय न किया जाये, किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाय।

किसी भी स्तर पर मिलावट नकली अपमिश्रण युक्त रसायनिक खाद किसी भी विक्रेता के द्वारा विक्रय किया जा रहा है तथा पीओएस मशीन का संचालन नहीं किया जा रहा है एवं विक्रेता द्वारा जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रियन्ट बिना बिल के तथा बिना स्टाक रजिस्टर पर इन्ट्री के स्टाक पाया जाता है तो उसके विरूद्व एफआईआर दर्ज करायी जाय।

यदि उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो जिला कृषि अधिकारी को अवगत करायें तथा जिला कृषि अधिकारी तुरन्त अपेच्छित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अर्न्तगत कार्यवाही करें।

यू.एस.अवस्थी
भारत का फर्टिलाइजर मैन

श्याम सुन्दर भाटिया

वह मुस्कराते हैं तो मानो देश के करोड़ों धरती-पुत्रों के चेहरे चमक रहे हैं। रातों को उनके ख्वाबों में हरियाली-हरियाली ही नजर आती है। अल सुबह वह उठते हैं तो आँखों में खेतों की ओर कूच करते किसान नजर आते हैं। साँसों में खेतों की माटी और फसलों की खुशबू आती है तो बात-बात में खेत-खलिहान, हल, बैल, ट्रैक्टर, फसल, खाद, पैदावार, कैसे हों और उन्नत देश के काश्तकार, कैसे हो कर्ज मुक्त इनकी आय दुगुनी सरीखे सवाल और जवाब का मिश्रण होता है।

देश का कोई ऐसा सूबा नहीं बचा, जहाँ उनके कदम न पड़े हों। हिंदुस्तान के करोड़ों-करोड़ धरती-पुत्रों ने फरिश्ते के तौर पर जानते और मानते हैं किसानों को मालूम है, उनके हर दर्द की दवा वही ही हैं। जी हाँ, हम इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानि 'इफ्को' के प्रमुख डा. उदय शंकर अवस्थी की ही बात कर रहे हैं। उन्नत किसान-सुदृढ़ भारत के लक्ष्य को समर्पित डा. अवस्थी 27 वर्षों से इफ्को के मुखिया हैं। इन्होंने अपने जोश, जुनून और संकल्प के बूते इफ्को को दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कंपनी बनाकर कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया।

इफ्को को फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया। इफ्को से 40 हजार से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी और देश के साढ़े पाँच करोड़ काश्तकार जुड़े हैं। इफ्को भारत की ही नहीं बल्कि, पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शामिल होती है।

यूपी के छोटे से गाँव में 12 जुलाई, 1945 को स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में जन्में दूरदर्शी इस टेक्नोक्रेट को 2006 में धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय ने पीएचडी से सम्मानित किया गया। ग्रीनटेक सेफ्टी अवॉर्ड, बेस्ट सीईओ अवॉर्ड, डेविडसन फ्रेम अवॉर्ड जैसे दर्जनों विश्व प्रसिद्ध पुरस्कारों और सम्मानों से उन्हें अब तक नवाजा जा चुका है। कृषि जगत में विशिष्ट पहचान रखने वाले फर्टिलाइजर मैन के नाम से मशहूर डा.यूएस अवस्थी फेम इण्डिया पत्रिका-एशिया पोस्ट सर्वे के 50 प्रभावशाली व्यक्ति-2020 की सूची में 40वें स्थान पर हैं।

फर्टिलाइजर मैन वैसे तो शुरुआत से ही भावनात्मक होने के साथ-साथ मेधावी भी थे, परन्तु बीएचयू के परिवेश ने उन्हें एक दूरदर्शी टेक्नोक्रेट बनने में मदद की। इफ्को प्रमुख ने 1966 में बीएचयू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल की। इस दौरान देश चीन के साथ युद्ध, भीषण अकाल के दौर से गुजर रहा था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने देश की जनता से जय

जवान-जय किसान नारा बुलंद करने की अपील की। हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं थे। देश हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहा था। इस माहौल का उदय शंकर अवस्थी की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। श्री अवस्थी ने बतौर छात्र यह शिद्दत से महसूस किया, उन्नत काश्तकार ही सशक्त देश की नींव बन सकता है। उन्होनें देश के लिए एक बड़े बदलाव के वाहक बनने का सपना देखा।

कृषि जगत में विशिष्ट पहचान रखने वाले फर्टिलाइजर मैन के नाम से मशहूर डा.यूएस अवस्थी फेम इण्डिया पत्रिका-एशिया पोस्ट सर्वे के 50 प्रभावशाली व्यक्ति-2020 की सूची में 40वें स्थान पर है।

कैमिकल इंजीनियरिंग के बाद वह फर्टिलाइजर इण्डस्ट्री में आ गए। यहीं से उनके सपनों को पंख मिले। श्रीराम फर्टिलाइजर में पांच वर्ष की सेवाओं के दौरान उन्होंने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के समन्वय की बारीकियों को सीखा। 1971-76 तक पांच साल बिड़ला ग्रुप में रहे। गोवा में पोस्टिंग के दौरान विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाने भी लगे। डा. अवस्थी की पहचान प्रोफेसर के तौर पर भी हो गयी। 1976 में इफ्को के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर पॉल पाटन के साथ काम करने का मौका मिला। वह 10 वर्षों तक इफ्को के विभिन्न प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे।

इस लम्बी अवधी में उन्होनें कोऑपरेटिव की ताकत और भविष्य की संभावनाओं को परखा और समझा। इस बीच डा. अवस्थी की पहचान यूथ एक्टिव टेक्नोक्रेट के साथ-साथ सुलझे हुए इंटरप्रेन्योर की भी हो गई। नतीजन मात्र 41 वर्ष की आयु में 1986 में पीपीसीएल के सीईओ बन गए। भारत के किसी भी कोरपोरेट हाउस ने इससे पहले किसी को अपना सीईओ नहीं बनाया था। 1993 में डा. अवस्थी को फिर इफ्को से बुलावा आया तो मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई । हालॉकि इफ्को का ऑफर मौजूदा पगार से कम था। बावजूद इसके उन्होनें हां कर दी और इफ्को के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए। इफ्को के मुखिया के तौर पर ढ़ेर सारी चुनौतियाँ सामने रहीं। एक ओर मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच की दूरी मिटानी थी तो दूसरी ओर कर्ज देने वाले बैंकों की दखल अंदाजी भी खत्म करनी थी। नई टेक्नोलॉजी लाने और प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने की अलग चुनौती थी। इन्होनें इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। एक प्रोफेशनल्स मजबूत टीम तैयार की। कोऑपरेटिव सोसाइटी और धरती पुत्रों को साथ जोड़ने के लिए देशभर में लम्बी-लम्बी यात्राएं कीं। इफ्को के आधुनिकीकरण के साथ विजन 2000 का श्रीगणेश हुआ। इफ्को के चार प्लांटों की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई गई। सभी प्लांटों में एडवांस टैक्नोलॉजी पर जोर दिया ताकि वे एनर्जी सेविंग के साथ-साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी बनें। हर मोर्चे पर डा.अवस्थी को सफलता मिलती चली गई और लोग जुड़ते चले गए। टर्नओवर हो या नेटवर्थ या फिर नेशनल और इंटरनेशनल ज्वांइट वेंचर की बात-इफ्को ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

फर्टिलाइजर मैन मानते हैं, शहरों और गाँवों में रहने वाले लोगों के बीच एक खाई है, जिसे डिजिटल क्रांति के जरिए भरा जा सकता है। अगर गाँव के किसान और नौजवान स्मार्ट फोन के जरिए दुनिया से जोड़ दिए जाएं तो वे सिर्फ खेत नहीं बल्कि खेतों के बाहर भी अपने जीवन स्तर को सुधारने में बड़ी छलांग लगा सकते हैं।

डा. अवस्थी का शुरु से ही मानना रहा है, इफ्को का झंडा ऊंचा रहे, क्योंकि इस देश के किसानों का झंडा ऊंचा है, देश में सहकारिता का झंडा ऊंचा है। वह कहते हैं, लोग उन्हें जब बताते हैं कि इफ्को तो बहुत बड़ा ब्रांड है। देश की सबसे बड़ी सोसाइटी है, यह सुनकर सुकून मिलता है। **(लेखक श्याम सुन्दर भाटिया, वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्च स्कॉलर हैं। मो.न.7500200085 है।)**

रोजगार से जुड़ी जानकारी के लिए ग्राम पंचायत या विकास खण्ड कार्यालय से कर सकते हैं सम्पर्क

सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिये कामगारों की रूचि एवं कौशल के अनुरूप रोजगार व स्वरोजगार कार्य उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गांव में ही जीविकोपार्जन अन्य गतिविधियों के लिये रोजगार के अवसर भी प्रदान किये जा रहे हैं। ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधरोपण, जल संरक्षण एवं सिंचाई, आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, जल जीवन मिशन,

गरीब कल्याण रोजगार अभियान

सामुदायिक शौचालय कांप्लेक्स, वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, कूप निर्माण, सम्पर्क मार्ग, रेलवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, पी0एम0 कुसुम, जिला खनिज निधि से कार्य, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबधंन, खेत तालाब, पशुबाड़ा, बकरी बाड़ा, मुर्गी बाड़ा, खाद गढ्डा (वर्मी कम्पोस्ट), भारत नेट के तहत फाईवर आपटिक बिछानें के कार्य कराये जायेंगे। रोजगार की तुरन्त आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि रोजगार से जुड़ी जानकारी के लिये इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या विकास खण्ड कार्यालय से सम्पर्क कर सकता हैं।

अनूठी पहल: धनवंतरि रथ

अहमदाबाद नगर निगम 'गैर कोविड' मरीजों को पहुंचा रहा घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं

कोविड-19 महामारी के दौरान जहां कोविड स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है वहीं सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के अलावा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने धन्वंतरि रथ के माध्यम से एक अनूठी और अभिनव मिसाल कायम की गई है। धन्वंतरि रथ शहर में लोगों के घरों तक गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल मेडिकल वैन है। शहर के कई बड़े अस्पताल कोविड- 19 के मरीजों के उपचार के लिए समर्पित हैं, इसलिए मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग आदि से संबंधित गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी बंद रहने से लोग इस समय अस्पताल भी नहीं जा पा रहे हैं।

अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा शुरू की गई पहल में धन्वंतरि रथ के नाम से मोबाइल चिकित्सा वाहनों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इन चिकित्सा वाहनों में अहमदाबाद नगर निगम के शहरी स्वास्थ्य केंद्र के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के साथ आयुष चिकित्सक, चिकित्सा सहायक, और नर्सिंग स्टाफ होते हैं। ये चिकित्सा वाहन शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अहमदाबाद शहर में सभी लोगों को उनके घरों तक गैर-कोविड बीमारियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में ओपीडी सेवाएं और चिकित्सा परामर्श प्रदान कर रही हैं।

इन मोबाइल चिकित्सा वाहनों में सभी जरूरी दवाएं होती हैं जिनमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं, विटामिन की खुराक और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ बुनियादी परीक्षण उपकरण भी शामिल हैं। इन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अलावा, धन्वंतरि रथ ने कई वजहों से अस्पताल नहीं जा सकने वाले लोगों तक पहुंचकर उन लोगों की पहचान करने में मदद की जिन लोगों को आगे नैदानिक उपचार या आईपीडी भर्ती की आवश्यकता थी। इसके साथ ही धन्वंतरि रथ ने यह सुनिश्चित किया कि वे समय रहते अस्पताल पहुंच सकें। अहमदाबाद नगर निगम पूरे शहर में 120 धन्वंतरि रथ चला रहा है। धन्वंतरि रथ ने अब तक 4 लाख 27 हजार से अधिक लोगों को ओपीडी परामर्श दिए हैं। नगर निगम की इस पहल की मदद से बुखार के 20,143 से अधिक रोगियों तथा खांसी, ठंड और नजला के 74,048 रोगियों का इलाज किया गया। इस पहल से श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण वाले 462 से अधिक रोगियों को शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में नैदानिक उपचार के लिए भेजा गया। इसके माध्यम से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और ऐसी दूसरी बीमारियों से ग्रस्त अन्य 826 रोगियों को पास के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में उपचार के भेजा गया। धन्वंतरि रथों की तैनाती का कोविड-19 के रोगियों के उपचार पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है क्योंकि समय रहते इसके संक्रमण के कई छिपे मामलों की पहचान की जा सकी।

तेजी से आते मॉनसून के मौसम और इस मौसम में वेक्टर जनित रोगों के बढ़ने की संभावना को देखते हुए 15 जून, 2020 से इन मोबाइल चिकित्सा वाहनों की स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाकर इसमें मलेरिया और डेंगू के परीक्षणों को भी शामिल कर लिया गया है।

आगामी अंक

स्वतंत्रता विशेषांक

एक से 16 अगस्त 2020

विशेषांक में-

- स्वतंत्र भारत में कृषि विकास
- अन्नदाता ने बनाया आत्मनिर्भर
- उन्नत किसान, विकसित भारत लक्ष्य

ग्राम भारती

विज्ञापन दर

एक पूर्ण पृष्ठ (रंगीन): 20,000.00
एक पूर्ण पृष्ठ (सामान्य):10,000.00
आधा पृष्ठ (सामान्य): 05,000.00
चौथाई पृष्ठ (सामान्य): 02,500.00
(अंतिम पृष्ठ 100 प्रतिशत अतिरिक्त)

समस्त विज्ञापन मूल्य का भुगतान ग्राम भारती के नाम से बैंक ड्राफ्ट, चेक के माध्यम से करें।

A/c Pay Chaque/DD in Favour of "GRAM BHARTI"

For RTGS/NEFT: VIJAYA BANK A/c No. 710600301000328

IFSC Code: VIJB0007106

Branch-Hazratganz, Lucknow-226001

कोविड: पीएनबी का फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण अभियान

कोविड-19 की रोकथाम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पीएनबी आगे आया है। इस बैंक ने संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्य शुरु किया है। इसकी शुरुआत केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने की।

इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एस.एस.मल्लिकार्जुन राव और बैंक के के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें पीएनबी के देश भर में मौजूद 22 अंचल कार्यालयों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

राष्ट्रीय मुद्दों पर पीएनबी के योगदान की सराहना करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक है जिसकी स्थापना राष्ट्रवाद की भावना के साथ की गई थी और यह लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित था। यह भारतीय पूंजी के साथ शुद्ध रूप से भारतीय नागरिकों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है। उन्होंने बताया कि आजादी से पहले की अवधि के दौरान इस बैंक को जलियांवाला बाग समिति का खाते खोलने का गौरव हासिल है जिसे बाद में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संचालित किया गया था।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में है फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण की जिम्मेदारी को उठाने के लिए पंजाब नैशनल बैंक का आभार है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएनबी इस महामारी से निपटने की लड़ाई में सरकार के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। बैंक ने पीएम केयर फंड में दान देने और फेस मास्क तथा सैनिटाइजर के वितरणके लिए सीएसआर गतिविधियों के आयोजन जैसे कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल और हाथों की अच्छी तरह सफाई कोविड से निपटने में उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देता है और यह इस बीमारी से बचने के लिए फिलहाल मौजूद सबसे अच्छा सामाजिक टीका है।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पंजाब नैशनल बैंक पूरे देश में 662 जिलों में ऐसी सामग्री (फेस मास्क, सैनिटाइजर)वितरित कर रहा है और मैं पीएनबी को उनके इन प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।

ग्राम भारती पाक्षिक के लिए स्मामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सर्वेश कुमार सिंह द्वारा माडर्न प्रिन्टर्स, 10 घसियारी मण्डी, कैसरबाग,लखनऊ से मुद्रित एवं 103-117, प्रथम तल, प्रिंस काम्पलेक्स हजरतगंज, लखनऊ 226001 से प्रकाशित
सह संपादक:
देवेश कुमार त्रिपाठी
फोन: 9453272129
व्हाट्सएप: 9140624166
ई-मेल
grambhartilko@gmail.com